भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1773

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

घरेलू कोकिंग कोयला उत्पादन

1773. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित घरेलू कच्चे और कोकिंग कोयले की मात्रा कितनी है तथा अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इसके लिए क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आयात की तुलना में स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से घरेलू कोकिंग कोयले की मांग का कितना प्रतिशत पूरा किया जाता है;

(ग) इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा बढ़ाने हेतु 'मिशन कोकिंग कोल' के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कोकिंग कोयले के मिश्रण को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ङ) क्या ओडिशा राज्य सहित कोयला-उत्पादक क्षेत्रों में कोई निष्कर्षण, प्रसाधन या उत्पादन विस्तार पहल शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता को मजबूत करने में ऐसी पहलों का क्या संभावित योगदान है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) के दौरान जून 2026 तक कुल घरेलू कच्चे कोयले का उत्पादन 232.49 मि.ट. (अनंतिम) हुआ है, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन 13.32 मि.ट. (अनंतिम) हुआ है।

अगले तीन वित्त वर्षों के लिए कच्चे कोयले के उत्पादन लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

	वित्त वर्ष 2027	**वित्त वर्ष 2028**	**वित्त वर्ष 2029**	**वित्त वर्ष 2030**
लक्षित कोयला उत्पादन (मि.ट. में)	1112	1378	1450	1533

(ख) : इस्पात क्षेत्र भारत में कोकिंग कोयले का प्राथमिक उपभोक्ता है। इस्पात क्षेत्र में, कोकिंग कोयले की मांग का लगभग 10 प्रतिशत घरेलू कोकिंग कोयले के माध्यम से पूरा किया जाता है, जबकि लगभग 90% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

(ग) : कोकिंग कोयला मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति में निम्नलिखित शामिल हैं -

- वित्त वर्ष 2022 से 7.5 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की कुल क्षमता वाली 2 कोकिंग कोयला वाशरी प्रारंभ की गई हैं, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त वर्ष 2030 तक प्रारंभ करने के लिए 19.5 एमटीपीए की कुल क्षमता वाली 7 नई कोकिंग कोयला वाशरीज की योजना बनाई गई है।
- इस्पात क्षेत्र के लिए धुले हुए कोकिंग कोयला की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1 मौजूदा कोकिंग कोयला वाशरी का मुद्रीकरण किया गया है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 22 कोकिंग कोयला ब्लॉकों की नीलामी की गई है।
- कोल इंडिया लिमिटेड की 11 बंद हो चुकी कोकिंग कोयला खानों की शीघ्र प्रचालन के लिए राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को पेशकश की गई है।
- घरेलू कोकिंग कोयले के अधिक उपयोग की सुविधा और धुले हुए कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मार्च 2024 में गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी के तहत एक नया उप-क्षेत्र, "वाशरी डेवलपर एंड ऑपरेटर (डब्ल्यूडीओ) मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करते हुए इस्पात" शुरू किया गया था।

(घ) : कोकिंग कोयला सम्मिश्रण को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. वित्त वर्ष 2030 तक 19.5 एमटीपीए की कुल क्षमता के साथ सात नई कोकिंग कोयला वॉशरीज का विकास।
ii. मौजूदा वाशरियों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण,
iii. इस्पात क्षेत्र में स्टाम्प चार्जिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, जो कोक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए घरेलू कोकिंग कोयले के उच्च सम्मिश्रण को सक्षम बनाता है। इन उपायों से वित्त वर्ष 2030 तक इस्पात उत्पादन में घरेलू कोकिंग कोल सम्मिश्रण लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत होने की अपेक्षा है।
iv. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को उन मामलों में मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों) के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

v. एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि को संशोधित कर 30 वर्ष कर दिया गया है।

vi. यह निर्णय लिया गया है कि ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तरों पर ध्यान दिए बिना कोयला उपलब्ध कराकर विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा किया जाए।

vii. एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयले का उपयोग करते हुए इस्पात' बनाया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी और देश में धुले हुए कोकिंग कोयले की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी।

viii. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

ix. गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के तहत हाल ही में सृजित की गई कोयला सेतु विंडो के तहत कोयला लिंकेज से देश में धुले हुए कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और परिणामस्वरूप कोयले के आयात में कमी आएगी।

(ङ) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के 95 कोकिंग कोल ब्लॉकों में से 84 ब्लॉकों का पूरी तरह से अन्वेषण कर लिया गया है, जबकि शेष 11 ब्लॉकों का अन्वेषण किया जा रहा है, इनका आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया है अथवा इनका क्षेत्रीय रूप से अन्वेषण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 से, सीएमपीडीआई ने केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएसएस) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) के तहत लगभग 143 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करते हुए 15 नए कोकिंग कोयला ब्लॉकों का अन्वेषण शुरू किया है।

इसके अलावा, दिनांक 30.06.2026 तक, 22 कोकिंग कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 13 ब्लॉक पूरी तरह से अन्वेषित थे और आवंटन के समय 09 का आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया था। आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों में से, 02 ब्लॉकों में अन्वेषण पूरा कर लिया गया है, जिससे लगभग 437 मिलियन टन भूवैज्ञानिक भंडार स्थापित हो गए हैं। ओडिशा राज्य में किसी भी कोकिंग कोयला धारक क्षेत्र चिन्हित नहीं किया गया है और न ही कोई कोकिंग कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2022 से 7.5 एमटीपीए की कुल क्षमता वाली 02 कोकिंग कोयला वाशरी चालू की गई हैं, 2 एमटीपीए की क्षमता वाली 01 मौजूदा कोकिंग कोयला वाशरी का मुद्रीकरण किया गया है और वित्त वर्ष 2030 तक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 19.5 एमटीपीए की कुल क्षमता वाली 07 नई कोकिंग कोयला वाशरी स्थापित किए जाने की अपेक्षा है।

****